लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 1-15 सितंबर 2022 www.haryanasamvad.gov.in अंक -49

"उस साहस को जानने का प्रयास करो जिसमें सच्चाई जानने की हिम्मत है, जीवन के सत्य को बताने की हिम्मत है।"
: विवेकानंद

हिंदी दिवस पर विशेष

3

हरियाणा की समृद्धि में वृद्धि करेगा हथिनीकुंड बांध

6

ई-गवर्नेंसः समय के साथ बढ़ते कदम

7

अत्याधुनिक एवं अलौकिक अमृता अस्पताल

विशेष प्रतिनिधि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े 'अमृता अस्पताल' का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया। इस मौके पर माँ अमृता आनंदमयी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां के आशीर्वाद का अमृत देश को मिल रहा है। फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। यह जितना आधुनिक है सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से उतना ही अलौकिक है। यहां आधुनिकता और अध्यामिकता का समागम देखने को मिल रहा है। यह गरीबों के लिए सुलभ और सस्ते इलाज का माध्यम बनेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए वे अम्मा के आभारी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश की दूसरी संस्थाओं के लिए ये प्रकल्प आदर्श बनेगा। अमृता अस्पताल के शुरू होने से न केवल फरीदाबाद और हरियाणा राज्य के लोगों सुविधा मिलेगी बल्कि दिल्ली एनसीआर को भी उपचार की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां अमृता आनंदमयी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से एक अलग लगाव है, उसी लगाव और प्रेम के चलते प्रधानमंत्री के आगमन को पूरा प्रदेश आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करता है। उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री गरीब एवं अभावग्रस्तों की चिंता करते हुए अंत्योदय दर्शन के साथ योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, जो सराहनीय है। गरीबों को छत प्रदान करना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना तथा 'हर घर नल से जल' जैसी योजनाओं की शुरुआत करना अंत्योदय दर्शन का बड़ा उदाहरण हैं।

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस

अस्पताल में 534 आईसीयू बेड सहित 2600 बेड होंगे और इसे 81 विशेष विभागों से लैस किया जाना है जो कि भारत में सर्वाधिक है। अस्पताल में 64 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। इसके अलावा, यहां 150 सीटों वाला पूरी तरह से आवासीय एमबीबीएस कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। एक नर्सिंग कॉलेज और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक कॉलेज भी होगा। यहां रक्त और अन्य महत्वपूर्ण नमूनों के प्रसंस्करण के लिए देश में सबसे बड़ी स्वचालित स्मार्ट लैब होगी।

पीएम ने की हरियाणा सरकार की प्रशंसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार के कामकाज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है, जहां हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया है।

खेल के क्षेत्र में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का बखान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि फ़िटनेस और खेल जैसे विषय हरियाणा की रगों, मिट्टी और संस्कारों में हैं। यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी तरह दूसरे राज्यों को भी हरियाणा से प्रेरणा लेनी चाहिए और कम समय में ऐसे परिणाम हासिल करने चाहिए।

प्रधानमंत्री ने झज्जर में भी हरियाणा सरकार के नवोन्मेषी रुख और दूरदर्शिता की भी प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने इस समर्पण और नवाचार से काम किया कि हरियाणा सरकार के कार्य मों के कुछ मॉडल केंद्र सरकार ने अपनाए हैं। लाल डोरा मुक्त योजना की शुरुआत देश में सर्वप्रथम हरियाणा ने की थी, जिसे बाद में देशभर में स्वामित्व योजना के नाम से लागू किया गया। इसी तरह ऑनलाइन ट्रांसफर नीति, खेल नीति और कई अन्य हरियाणा सरकार के कार्य म हैं जिनका अनुसरण देश के अन्य राज्य कर रहे हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचारपूर्वक भेंट करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल

डॉक्टर, मनुष्य और ईश्वर के बीच सेतु

अमृता अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की फाउंडर मां अमृतानंदमयी देवी ने मलयालम भाषा में कहा कि डॉक्टर, मनुष्य और ईश्वर के बीच सेतु होते हैं। इसलिए डॉक्टर को अपने अंदर अद्भुत शक्ति रखनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे, वह आधुनिक चिकित्सा एवं आविष्कारों में रखते हैं।

उन्होंने कहा कि रोगी डॉक्टरों के पास वैसे ही आते हैं, जैसे भक्त भगवान के पास करूणा और राहत के लिए आते हैं। उसके लिए अस्पताल ही आश्रय स्थल होता है। उस वक्त डॉक्टर मरीज के लिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान होता है।

अम्मा ने कहा कि चिकित्सा सेवा में कार्यरत सभी, डॉक्टरों, नर्सों व अन्य कर्मचारियों के होठों पर सदैव मुस्कान होनी चाहिए। उनकी बोलचाल मरीज को सुख देने वाली हो। उनकी दृष्टि में विनय और नम्रता हो। एक डाक्टर को अच्छा श्रोता होना चाहिए। उसे रोगियों की मनःस्थिति को समझते हुए उनकी सेवाओं में सक्षम होना चाहिए। यह तभी संभव है जब स्वास्थ्य कर्मी अपने कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पित हों।

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त-दुरुस्त

हरियाणा की मनोहर सरकार शुरू से ही प्रदेश के मरीजों की सेहत का ख्याल रख रही है। ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां की जा रही हैं। सरकार सेहत को लेकर कितनी गंभीर है इस बात का अंदाजा कोरोना काल में लग गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस दौर में दिन देखा न रात। लंबे समय तक विभागीय अधिकारियों एवं डाक्टरों के साथ मिलकर लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया था।

स्वास्थ्य विभाग ने इसी पखवाड़े 800 से अधिक एमबीबीएस, डेंटल सर्जन व 2500 से अधिक नर्सिंग व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की हैं। भर्ती प्रक्रिया जारी है। इतना ही नहीं दवाइयों की खेप भी लगातार नागरिक अस्पताल, सीएचसी व पीएचसी तक पहुंचाई जा रही हैं।

स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है। 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कालेज थे, जो अब 13 हो गए हैं। आने वाले समय में इस कॉलेज समेत 9 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे। प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। वहीं प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 21 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा जाएगा। वर्ष 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 1500 करोड़ था जो अब बढ़कर 6500 करोड़ से पार चला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अलावा चिकित्सा शिक्षा, आयुष तथा आयुष्मान भारत योजना के संचालन संबंधित कार्यों पर अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जाती हैं।

हरियाणा अब पोलियो फ्री हो चुका है, अब टीबी फ्री होने की ओर अग्रसर हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश को एनीमिया से मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा जिससे विशेषकर महिलाओं व बच्चों को काफी लाभ होगा।

'मिशन टीबी फ्री हरियाणा' के तहत विभिन्न कॉरपोरेट कंपनियों ने प्रदेश के 11 जिलों को अडॉप्ट किया गया है। इनमें यमुनानगर और करनाल जिला को राइट्स कंपनी, पानीपत को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सोनीपत को हिंदुस्तान लीवर, हिसार को जिंदल ने, मेवात को आर जे कॉर्प लिमिटेड , फरीदाबाद को एस्कोर्ट कंपनी, महेन्द्रगढ़ व रेवाड़ी को हीरो मोटोकॉर्प ने अडॉप्ट कर रखा है। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी प्रदेश के दो जिले पलवल और झज्जर अडॉप्ट करने की सहमति जताई है। प्रदेश के 9 जिले शेष रहते हैं जिनमें सिरसा, फतेहाबाद, जींद, अंबाला, पंचकूला , रोहतक, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी व भिवानी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉरपोरेट कंपनियों से आह्वान किया कि वे देश को सन् 2025 तक टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के जिलों को अडॉप्ट करें।

- मनोज प्रभाकर

संपादकीय

संकल्पों का पखवाड़ा

वैसे हर पखवाड़ा संकल्पों का पखवाड़ा होता है। एक सितम्बर से 15 सितम्बर का पखवाड़ा दो महत्वपूर्ण संकल्पों की याद दिलाएगा। पहला है 'शिक्षक दिवस' (5 सितम्बर) और दूसरा हिंदी दिवस (14 सितम्बर) वैसे हर हर वर्ष की भांति ये तारीखें भी बीत जाएंगी और हम कुछ औचारिकताएं पूरी करने के बाद इन तारीखों के महत्व को भूल जाएंगे। लेकिन इस बार ये संकल्प दिवस कुछ गंभीर चिंतन मांगते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि आज़ादी के अमृत-महोत्सव वाले वर्ष हमें उन शिक्षकों को भी याद करना है जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम एक स्वतंत्र देश में प्राप्त वातावरण में अपने संघर्ष से अपने लिए सम्मानजनक स्थान बना सकें और देश के समग्र विकास में अपना योगदान दे सकें। द्रोणाचार्य, संदीपनी, वेदव्यास, गुरु वाशिष्ठ का पौराणिक महत्व आज शताब्दियों बाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन हमारे अपने वर्तमान परिवेश में प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हमें गुरुओं का मार्गदर्शन मिलता रहा है, मगर कभी-कभी विचार अवश्य करना चाहिए कि क्या हमने अपने सुख दुख में उन्हें स्मरण किया? इस बार का शिक्षक-दिवस हमें निजी रूप में अपने-अपने शिक्षकों की स्मृतियों को समर्पित करना चाहिए।

दूसरा है 'हिन्दी दिवस' का महत्व। हमें भीतर तक यह बात कचोटती होगी कि हमें 75 वर्ष बाद भी अपनी इस भाषा को उसका समुचित सम्मान व स्थान नहीं दे पा रहे हैं। पूरे विश्व में अधिकांश देश अपनी स्थानीय एवं मातृभाषाओं में ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं और ऐसे देश में विकास की गति तीव्र रही है। हमारे देश में अभी भी शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं बन पाई। यद्यपि हरियाणा में सरकारी अब पूरी गंभीरता से इस दिशा में प्रयासरत है कि कुछ विषयों की पढ़ाई तो अनिवार्य रूप में हिंदी में ही कराई जाए। इसके लिए आवश्यक है कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक विषयों में सरल भाषा में पाठ्यक्रम की पुस्तकें प्राप्त हों। सरकार अपनी ओर से इस दिशा में प्रयासरत भी है। इस बार हम भी अपने-अपने स्तर पर कुछ गंभीर चिंतन करें तो हमारा विकास भी गति पकड़ेगा। इस दिशा में राजस्थान, बिहार व मध्यप्रदेश में कुछ सफल प्रयोग भी हुए है और हरियाणा भी इस दिशा में एक सकारात्मक बदलाव की ओर अग्रसर है। अपने सुझाव हमें भी भेजें और निजी स्तर पर भी प्रयास अवश्य करें।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

स्थानीय निकायों के सहयोग से होगा सड़कों का विकास

शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा

प्रदेश के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा। यानी सड़कों के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत बजट राज्य सरकार की ओर से तथा 50 प्रतिशत खर्च स्थानीय निकाय को करना होगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को आयोजित प्रेस वार्ता में यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहरों में जनता की मांगों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 506 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिस पर 141 करोड़ रुपए खर्च आएगा। निकायों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आगामी 15 दिनों में प्रस्तावित सड़कों का टेंडर जारी करें।

कृषि विपणन बोर्ड बनाएगा सड़कें

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से प्रदेश में लगभग 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कें बनाई जानी हैं, जिन पर लगभग सवा 425 करोड़ रुपए खर्च आएगा। नई सड़कें डब्ल्यूबीएम के स्थान पर ब्लैक टॉप तकनीक से बनाई जाएंगी। इन सड़कों पर पानी नहीं भरेगा और यातायात भी सुगम रहेगा।

गौरतलब है कि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कें मार्केट फीस के रूप में अर्जित आय से बनाई जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मार्केट फीस से होने वाली आय में कमी आई है, इसलिए इन सड़कों के निर्माण हेतु एचआरडीएफ फंड से बिना ब्याज के 150 करोड़ रुपए विपणन बोर्ड को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक मंडियों तक जाने वाली सभी सड़कें बन जाएंगी। नई सड़कें बनने के बाद उनका रखरखाव जिला परिषद को सौंप दिया जाएगा।

सभी 90 हलकों में बनेंगी सड़कें

मुख्यमंत्री ने कहा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के संबंध में विधायकों से मांग और सुझाव लिए गए हैं। इसके अनुरूप लोक निर्माण विभाग द्वारा आगामी डेढ़ साल में कुल 2750 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, जिस पर लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 112 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं या उनका टेंडर हो चुका है। इनके निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च आएगा।

बिजली डिफॉल्टर्स उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली डिफॉल्टर्स उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना-2022 की घोषणा की, जिसके तहत ऐसी उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन किस्तों में कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यह योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्ट बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जो 31 दिसंबर, 2021 को और उसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे हैं। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, यदि वे मामला वापिस ले लेते हैं तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी।

11 नवंबर तक अग्निवीरों की भर्ती

तीन सिंतबर तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

भारत सरकार की 'अग्निपथ' योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए सेना भर्ती मुख्यालय, अंबाला छावनी, खडगा स्टेडियम में 25 अक्तूबर से 11 नवंबर तक 'भर्ती रैली' का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में छह जिलों नामतः अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तथा पंचकूला और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के युवा भाग ले सकेंगे।

सेना भर्ती मुख्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल बी.एस.बिष्ट ने बताया कि अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर कलर्क, स्टोर कीपर (तकनीकी), अग्निवीर (तकनीकी), अग्निवीर ट्रैडसमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी।

योग्यताः अग्निवीर सामान्य डयूटी के लिए उम्मीदवार 10वीं कक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ और प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक तथा सीबीएसई के उम्मीदवार के लिए ओवरआल सी-2 ग्रेड या 45 प्रतिशत होना जरूरी है और प्रत्येक विषय में डी ग्रेड से कम नही होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ तथा प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत से कम अंक नही होने चाहिए। अग्निवीर (तकनीकी) के लिए 12वीं (विज्ञान) 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास जबकि अग्निवीर ट्रैडसमैन में ट्रैडस के अनुसार 10वीं व 8वीं पास की शर्त होगी। हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस वाले उम्मीदवारों को ड्राइवर आवश्यकताओं के लिए वरीयता दी जाएगी।

अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर (तकनीकी) के लिए कद 162 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम और छाती 77-82 सेंटी मीटर, अग्निवीर सामान्य डयूटी व अग्निवीर अन्य श्रेणी के लिए कद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन व छाती में इनको रहेगी छूटः कर्नल बिष्ट ने बताया कि भर्ती नियमावली के मुताबिक सेवारत, सेवानिवृत, सैनिक वीर नारियों के पुत्रों को कद, वजन और छाती में छूट दी जाएगी और परीक्षा में पास होने पर 20 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए एक बार के उपाय के रूप में अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17.5 वर्ष से 23 वर्ष निर्धारित किया गया है। पहली अक्टूबर, 2022 को पात्र उम्मीदवार आयु निर्धारित करने की प्रभावित तिथि के रूप में लिया जाएगा।

सेना में भर्ती निःशुल्क, निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर है। अधिक जानकारी के लिए www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट का अवलोकन किया जा सकता है।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

महाविद्यालयों में स्थानांतरण नीति में संशोधन

योग्य प्रोफेसर 15 महाविद्यालयों की भर सकेंगे पसंद

हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए संशोधित आनलाइन स्थानान्तरण नीति-2022 तैयार की है। इस नीति के तहत निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से स्थानान्तरण किए जाएंगे।

यह स्थानांतरण नीति अधिसूचना की तारीख से लागू होगी और स्थानांतरण नीति के तहत सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत उन सभी असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरों पर लागू होगी, जिनके विषय में 80 या 80 से अधिक स्वीकृत पद हैं। उन्होंने बताया कि योग्य प्रोफेसर 15 सरकारी महाविद्यालयों की अपनी पसंद भर सकेंगे। लेकिन विकल्प देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके विषय उन महाविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं और कार्यभार के अनुसार रिक्ति उपलब्ध है।

असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरों, जिनकी अनिवार्य ग्रामीण सेवा लम्बित है, उन ग्रामीण महाविद्यालयों के चयनों को भरना सुनिश्चित करेंगे जहां विषय पढ़ाया जा रहा है, ऐसा न करने पर सिस्टम आटोमेटिक ही प्राध्यापकों द्वारा भरे गए शहरी महाविद्यालयों के चयन (विकल्पों) को अस्वीकार कर देगा। स्थानांतरण नीति मौजूदा एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों (एएनओ) पर लागू नहीं होगी। यदि कोई एएनओ इस नीति के माध्यम से स्थानांतरण में भाग लेना चाहता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि ऐच्छिक कॉलेज में उसके शिक्षण विषय में एएनओ (एनसीसी) की पद रिक्ति हो।

जिला नूह (मेवात) और जिला पंचकूला (केवल मोरनी हिल्स क्षेत्र के लिए) में सरकारी महाविद्यालयों का चयन करने वाले असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरों का यह गृह जिला नहीं है, उन्हें अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिनों के भीतर म्यूचुअल ट्रांसफर विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफर पांच साल की अवधि के लिए वैध होगा और यदि कोई पद पर कार्यरत प्राध्यापक सेवानिवृत्त हो जाता है, तो अन्य पदधारी को समय सीमा के बावजूद अगले ऑनलाइन स्थानांतरण में भाग लेना होगा।

हर वर्ष 31 मार्च को कार्यभार के अनुसार वास्तविक रिक्तियों, मानी गई रिक्तियों और काल्पनिक रिक्तियों के लिए योग्यता तिथि, वेटेज/अंकों की गणना होगी। इसके अलावा, वास्तविक रिक्तियां, डीम्ड रिक्तियां और नोशनल रिक्तियां प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक की जाएंगी। पात्र असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर प्रत्येक वर्ष 1 मई से 15 मई तक 15 सरकारी महाविद्यालयों की अपनी पसंद ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं और विकल्प देते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उन महाविद्यालयों में उनके विषय पढ़ाए जा रहे हैं और संबंधित विषय में रिक्ति उपलब्ध हो। स्थानांतरण आदेश एक जून तक जारी किए जाएंगे।

असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर का स्थानांतरण पद के आवंटन/रिक्ति के लिए योग्यता मानदंड किसी कर्मचारी को रिक्त पद के आवंटन के लिए योग्यता निर्धारित 100 अंकों में से अर्जित कुल समग्र स्कोर/अंकों पर आधारित होगी। किसी रिक्ति के विरुद्ध प्राध्यापकों के दावे का निर्णय करने के लिए आयु पहला मानदंड होगा और इसमें कुल 100 अंकों में से अधिकतम 57 अंक होंगे। समान अंक होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठ होने वाले प्राध्यापकों को वरीयता दी जाएगी ।

ऐसे असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर जो 75 प्रतिशत से अधिक नेत्रहीन हैं या 75 प्रतिशत से अधिक लोकोमोटिव विकलांग हैं, जिनमें दोनों पैरों को शामिल किया गया है, उन्हें उनकी पसंद के स्टेशनों पर पोस्टिंग दी जाएगी और उन पर पांच साल के ठहरने की शर्त लागू नहीं होगी। समान अंक होने की स्थिति में आयु में वरिष्ठता को वरीयता दी जाएगी।

-संवाद ब्यूरो

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के सामान की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक का निरीक्षण किया। उन्होंने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुरानी दिल्ली रोड पर बनाए गए 731 मीटर लंबे फोरलेन फ्लाईओवर व सर्विस रोड को खुलवा दिया है।

हिंदी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें

- आजादी मिलने के दो साल बाद 14 सितबंर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
- हिंदी मंदारिन, स्पैनिश, इंग्लिश के बाद विश्व की चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है।
- दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी देश है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है।
- भारत, फिजी के अलावा मॉरीशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूगांडा, सिंगापुर, नेपाल, गुयाना, सुरिनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही सही, हिंदी बोली और समझी जाती है।
- हिंदी विश्व के तीस से अधिक देशों में पढ़ी-पढ़ाई जाती है, लगभग 100 विश्वविद्यालयों में उसके लिए अध्यापन केंद्र खुले हुए हैं। अमेरिका में लगभग एक सौ पचास से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन-पाठन हो रहा है।
- ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की 'वर्ल्ड इंग्लिश एडिटर' डेनिका सालाजार के अनुसार अब तक हिंदी भाषा के करीब 1000 शब्दों को डिक्शनरी में जगह मिल चुकी है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी (शब्दकोश) हर साल भारतीय शब्दों को जगह दे रही है।

मनोज प्रभाकर

हिंदी हमारी 'मां' है। और कहते हैं मां के पैर के नीचे स्वर्ग होता है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि हिंदी न केवल हमारे संवाद का माध्यम है बल्कि हमारी संस्कृति एवं प्रगति का मूल आधार भी है। इसके बिना सहज, सरल एवं सुसंगठित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह वही हमारी मातृभाषा है जिसने आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इसी 'मां' ने भारत मां के क्रांतिवीरों व नेताओं को एकजुट होने का पाठ पढ़ाया। राष्ट्रभक्ति के विचारों को जनसाधारण के मन तक पहुंचाने का काम किया। दिलों में अलख जगाई और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने का जोश पैदा किया।

रामप्रसाद बिस्मिल, भारतेंदू हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुब्रमण्यम भारती, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंशराय बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि अनेक महान कवि हुए जिन्होंने अपनी हिंदी साहित्य की रचनाओं के जरिए देश के लोगों को जागरूक करने का काम किया। बिस्मिल की रचना- 'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है..' आज भी गाई और गुनगुनाई जाती है।

आजादी के आंदोलन में गांधी ने भी हिंदी पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से कहा था कि वे हिंदी में भाषण दें एवं परिचर्चा करें ताकि सुदूर क्षेत्र तक उनकी आवाज़ पहुंच सके। बापू जी ने हिंदी की पत्रिका 'नवजीवन' का संपादन भी किया था।

देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से इस संदर्भ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्तमान शासकीय व्यवस्था का मानना है कि भारत देश भाषाई पहलू से भी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने। अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हो चुके हैं तो अंग्रेजी से मुक्ति क्यों नहीं? अंग्रेजी की निर्भरता को समाप्त किया जाए। इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति-2022 लागू की है। इस नीति में हिंदी को पूरी तवज्जो दी गई है। पाठ्क्रमों में हिंदी को प्रमुखता से शामिल किया गया है ताकि उसे तकनीकी भाषा का दर्ज़ा दिया जा सके। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग व अन्य संकायों की वाहक बने। ऐसा प्रयास किया गया है। ऐसा होने से देश में अनेकों अनेक प्रतिभाएं निखरकर सामने आएंगी। बौद्धिक संपदा का पलायन रुकेगा तथा देश प्रगति के मार्ग पर और तेजी से अग्रसर होगा।

हिंदी रोजगार की भाषा बन चुकी है। बहुत सी विदेशी कंपनियों ने भारत के बाजार में प्रवेश करने के लिए अपने कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए कहा है। इतना ही नहीं हिंदी पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। विदेशी कंपनियों को पता है कि जब तक उनके उत्पाद की जानकारी भारत के जन सामान्य को नहीं होगी वे कोई धेला नहीं कमा पाएंगी। विदेशी ही क्यों देशी कंपनियां भी अपने उत्पाद के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं।

कारोबार करने वाली लगभग कंपनियां हिंदी पर आश्रित हैं। इतना ही नहीं बहुत सी सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों ने तो स्थानीय बोली को भी अपने विज्ञापनों में जगह देना शुरू कर दिया है। हरियाणवी बोली को मास्टर स्ट्रोक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तथा फिल्म जगत में तो हरियाणवी बोली को सफलता का सूत्र माना जाने लगा है। इसी के चलते हाल ही में अनेक फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों को हरियाणवी बोली पर फोकस किया है। हिंदी की नानी कही जाने वाली हरियाणवी सात समंदर पार अपने जलवे बिखेर रही है। अमृत महोत्सव श्रंखला के तहत प्रदेश के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दे रहे हैं।

हिंदी आज सरकारी कामकाज की भाषा बन गई है। शासकीय प्रयोजन में हिंदी को अनिवार्य किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने तो इस बारे में अधिसूचना भी जारी की है कि सभी सरकारी कार्यालयों में पत्राचार व अन्य प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। हालांकि इसमें कुछ प्रगति कम हुई है जिस पर और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएं तथा हिंदी में कामकाज करने वालों के लिए पुरस्कार शुरू किए जाएं। 'मां' की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से देश व प्रदेश की प्रगति एवं समृद्धि के अनेक स्रोत खुलेंगे।

संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचाने के प्रयास

किसी भी देश की भाषा और संस्कृति उस देश में लोगों को जोड़े रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हिंदी और देवनागरी के मानकीकरण की दिशा में अनेक क्षेत्रों में प्रयास हुए हैं। हिंदी पूरे देश की न केवल सम्पर्क भाषा है बल्कि देश की एकता बनाये रखने में हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी विश्व की प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ हमारी राजभाषा भी है। इसीलिए मातृ भाषा हिंदी को सम्मान देने के लिये प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है।

हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली राज्यों की राजभाषा भी है। राजभाषा बनने के बाद हिंदी ने विभिन्न राज्यों के कामकाज में लोगों से सम्पर्क स्थापित करने का अभिनव कार्य किया है। लेकिन विश्व भाषा बनने के लिए हिंदी को अब भी संयुक्त राष्ट्र के कुल सदस्यों के दो तिहाई देशों के समर्थन की आवश्यकता है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उम्मीद है कि शीघ्र ही हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा में शामिल कर लिया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश यात्रा के दौरान अधिकतर सम्बोधन हिंदी भाषा में ही देते हैं। जिससे हिंदी भाषा का महत्व विदेशी धरती पर भी बढ़ने लगा है।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।
अंग्रेज़ी पढ़ि के जदपि, सब गुन होत प्रवीन।
पै निज भाषाज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।।
उन्नति पूरी है तबहिं जब घर उन्नति होय।
निज शरीर उन्नति किये, रहत मूढ़ सब कोय।।
निज भाषा उन्नति बिना, कबहुं न हैं सोय।
लाख उपाय अनेक यों भले करो किन कोय।।
इक भाषा इक जीव इक मति सब घर के लोग।
तबै बनत है सबन सों, मिटत मूढ़ता सोग।।
और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात।
निज भाषा में कीजिए, जो विद्या की बात।।
तेहि सुनि पावै लाभ सब, बात सुनै जो कोय।
यह गुन भाषा और महं, कबहूं नाहीं होय।।
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार।
सब देसन से लै करहू, भाषा माहि प्रचार।।
भारत में सब भिन्न अति, ताहीं सों उत्पात।
विविध देस मतहू विविध, भाषा विविध लखात।।
सब मिल तासों छांड़ि कै, दूजे और उपाय।
उन्नति भाषा की करहु, अहो भ्रातगन आय।।

- भारतेंदु हरिश्चंद्र

प्रदेश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए बेहतरीन खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। बीते पौने आठ वर्षों में प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर लगभग 526 करोड़ की राशि खर्च की गई।

बच्चों में खेल संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 1,100 खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इससे राज्य के लगभग 25,000 नवोदित खिलाड़ी लाभान्वित होंगे।

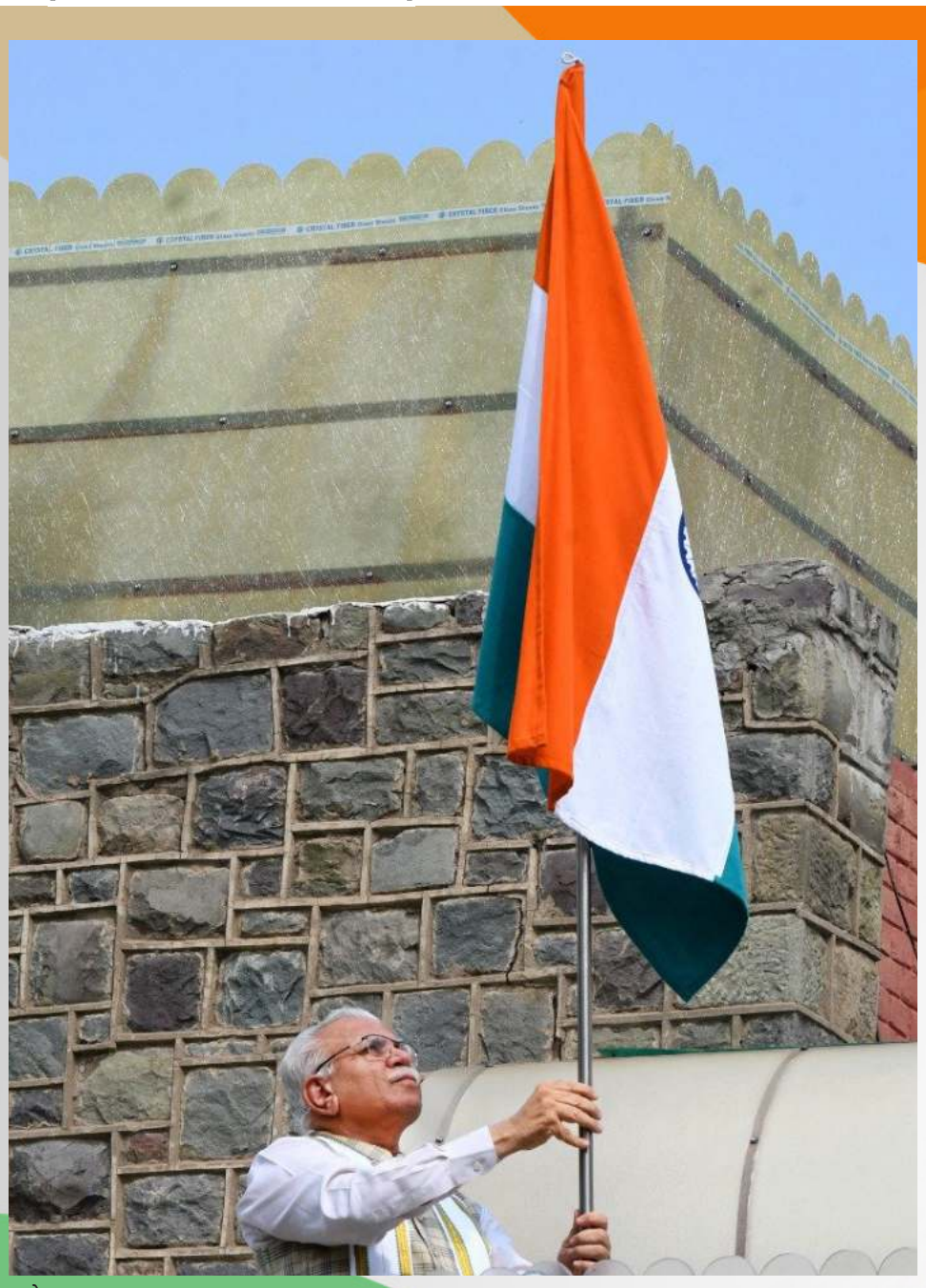

आन बा
नि

मनोज प्रभाकर

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में मनाये जा रहे 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत पूरे देश व प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में प्रदेश में दस हजार से अधिक कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं तथा इस वर्ष से अगले वर्ष तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

गौरतलब है कि 15 अगस्त, 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे हुए। इसी को ध्यान में रखते हुए 12 मार्च 2021 से 'आजादी का अमृत महोत्सव' अभियान की शुरुआत की गई थी। यह अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मनाए जाने वाले सभी कार्यं म उत्साह, एकता, राष्ट्रीय भावना व लोगों को साथ जोड़कर आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों से जुड़ना तथा इनमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना हम सबका कर्तव्य है। 13 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान का मूल उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करना था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित हुआ यह विशेष अभियान अपनी सार्थकता की छाप छोड़ गया। तीन रंगों से सजा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन-बान व शान है। यह हमारे घरों पर यूं ही फहराता रहे ताकि हमारे दिलों में देशभक्ति की भावना अनवरत बहे जो राष्ट्र की प्रगति का मूल आधार है।

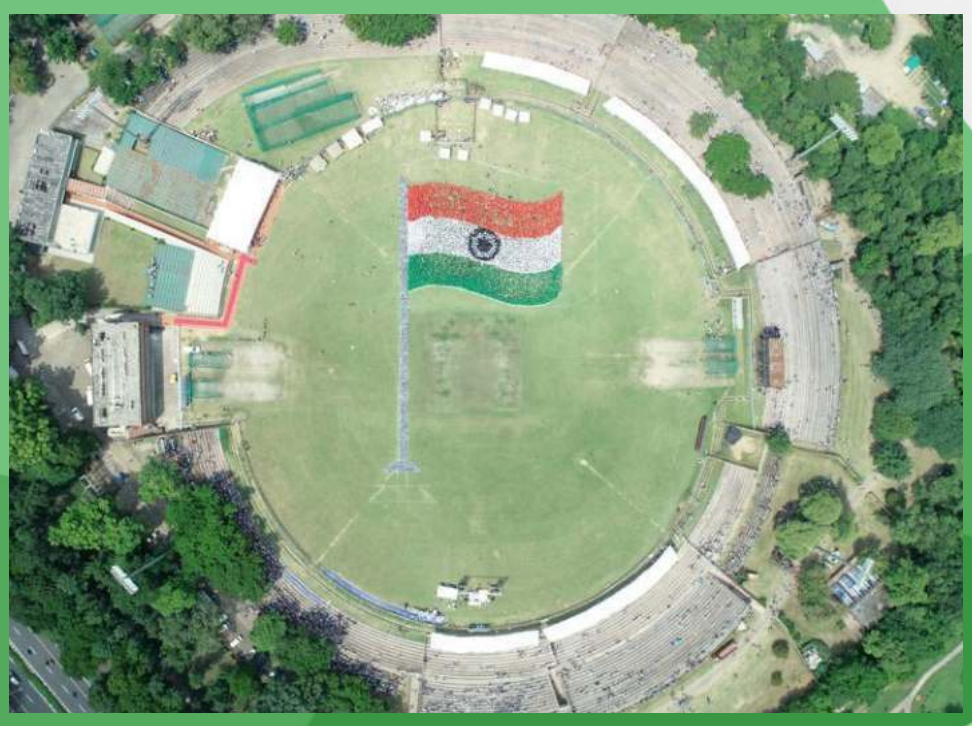

तिरंगा हर भारतीय का गौरवः मनोहर लाल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तिरंगा हर भारतीय का गौरव है। देशभक्ति को बढ़ावा देने और देश के प्रति अपने जज्बे को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हर घर तिरंगा' अनूठे अभियान की शुरुआत की थी। देशवासियों से आह्वान किया था कि वे 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। मुझे खुशी है कि सभी हरियाणावासियों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाकर इस अभियान में अपनी अहम भूमिका दर्ज की।

राज्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1857 का संग्राम 'वीर शहीद' एवं 'दास्तान-ए-रोहनात' नाटकों का मंचन हर जिले में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में अम्बाला छावनी में आधुनिक तकनीकों से युक्त शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। जन-भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर घर-हर परिवार तक दस्तक अभियान भी शुरू किया गया है।

अखंडता एवं देशभक्ति का प्रतीक

राष्ट्रीय ध्वज हमें स्वतंत्रता के लिए देश के लंबे संघर्ष की याद दिलाता है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह राष्ट्रवादियों के बीच एकजुटता का प्रतीक था और आज स्वतंत्र भारत में यह एकता, अखंडता एवं देशभक्ति का प्रतीक बन गया है। तिरंगा झंडा समान चौड़ाई के तीन रंगों से बना है। सबसे ऊपर केसरिया (केसरी), बीच में सफेद और नीचे हरा है। केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है तथा हरा रंग उर्वरता और वृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का धर्म चक्र 24 तीलियों से बना है। यह गति को दर्शाता है, जो लगातार प्रयासों और प्रगति का द्योतक है। यह 'कानून का पहिया' महान मौर्य सम्राट अशोक की सिंह राजधानी से लिया गया है, जिसे वाराणसी के पास सारनाथ में खोजा गया था।

राष्ट्रीय ध्वज न केवल हमारे राष्ट्रीय गौरव के रूप में खड़ा है, बल्कि एक प्रेरक शक्ति के रूप में भी कार्य करता है, जो हमें शक्ति , साहस, शांति, सच्चाई, उर्वरता, विकास और राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होना चाहिए। इसकी चौड़ाई से इसकी लंबाई का अनुपात दो से तीन है। संहिता अनुसार राष्ट्रीय ध्वज हाथ से बुने हुए ऊन/कपास/रेशम खादी से बना होना चाहिए।

राष्ट्रीय ध्वज के लिए हाथ से बुनी हुई खादी का निर्माण प्रारंभ में उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले के छोटे से गांव गराग में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संवैधानिक सभा की बैठक में आया। इसने पहली बार 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के डोमिनियन के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कार्य किया गया।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय ध्वज एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकय्या द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज पर आधारित है, जो महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे। उनका जन्म वर्तमान आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम के पास भाटलापेनुमरु में हुआ था।

आज 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के तहत जब हम हर घर में तिरंगा फहराते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह किसी भी रूप में क्षतिग्रस्त न हो ।

खेल मंत्री संदीप सिंह ने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की वेबसाइट लांच की। खेल फेडरेशन अपने खिलाड़ियों एवं उनसे जुड़ी जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड कर पाएंगी ताकि भविष्य में खिलाड़ियों को संबंधित सुविधाएं मिल सकें।

उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेशभर में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं। सरकार ने प्रत्येक विधानसभा की सड़कों के सुधार व मज़बूती के लिए 25-25 करोड़ राशि का प्रावधान करने का फैसला लिया है।

न शान

ंगा

नेता जी को श्रद्धांजलि

यह आजादी से पहले का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। 30 दिसंबर 1943 को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्र भारत का हिस्सा घोषित किया, और उनका नाम बदलकर 'शहीद-द्वीप' और 'स्वराज-द्वीप' कर दिया। इस अवसर पर आजाद हिंद सरकार के प्रधान मंत्री के रूप में नेताजी द्वारा पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड (अब नेताजी स्टेडियम) में भारतीय तिरंगा फहराया गया था। बाद में, भारतीय राष्ट्रीय सेना के जनरल ए डी लोगनाथन को क्षेत्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इस उपलब्धि के साथ, आजाद हिंद सरकार केवल निर्वासित सरकार नहीं रह गई, बल्कि उसकी अपनी जमीन, अपना गान, नागरिक संहिता, टिकट, रेडियो स्टेशन, बैंक और प्रशासन अन्य अंग थे। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि आजाद हिंद सरकार का गान हमारे वर्तमान राष्ट्रगान से काफी मिलता-जुलता था। गान के रूप में पढ़ा गयाः शुभ, सुख, चैन की बरखा बरसे, भारत भाग्य है...। आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर 30 दिसंबर 2018 को फास्ट फॉरवर्ड, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हार्दिक श्रद्धांजलि देने और उनकी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए पोर्ट ब्लेयर में फिर से तिरंगा फहराया था। उन्होंने नील और हैवलॉक द्वीपों का नाम बदलकर 'शहीद द्वीप' और 'स्वराज द्वीप' कर दिया, जबकि रॉस द्वीप का नाम 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप' रखा गया। आज वहां 150 फुट लंबा तिरंगा हमारे प्यारे नेता को देश की भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा है।

विजय का प्रतीक तिरंगा

तिरंगा हर क्षेत्र में हमारी जीत का शक्ति शाली प्रतीक बन गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की तमाम खेल प्रतिस्पर्धाओं में तिरंगा खिलाड़ियों में उत्साह एवं जुनून का संचार करता है। विजय हासिल होने पर तिरंगे का लहराव राष्ट्रीय गौरव की पराकाष्ठा तक ले जाता है। देश- विदेश में संगीत कार्यक्रम हो अथवा विज्ञान में उपलब्धि, तिरंगा फहराकर ही जीत का जश्न मनाया जाता है।

जिस समय भारत ने 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस समय की प्रत्येक विजयी घटना को तिरंगा फहराने से चिह्नित किया गया है। तब से यह हमारी जीत का एक औपचारिक प्रतीक बन गया, जो प्रत्येक भारतीय को देशभक्ति के एक सूत्र में बांधता है। चाहे वह 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध हो या 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति का अवसर या 1999 में कारगिल में ऑपरेशन विजय, भारत की जीत को हमेशा आसमान में तिरंगा फहराकर मनाया गया।

अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया तथा जब नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो राष्ट्रीय ध्वज गौरव का प्रतीक बना। इसी तरह, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 में पहली बार विश्व कप जीता, तो तिरंगे की ऊंची उड़ान के माध्यम से गर्व और उत्सव की भावना परिलक्षित हुई थी। इतना ही नहीं भारत ने जब पहला टी -20 विश्व कप जीता, तो तिरंगे में गर्वित राष्ट्र की भावनाओं को समान प्रतिबिंब मिला। चंद्रयान, या मंगलयान के सफल प्रक्षेपण पर, तिरंगा ने फिर से राष्ट्र की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया।

राष्ट्रीय ध्वज को आसमान में लहराने से देशभक्ति और एकजुटता की भावना परिलक्षित होती है। इस धारणा से प्रेरित होकर, भारतीय सेना ने 15 जनवरी, 2022 को जैसलमेर में 33,750 वर्ग फुट में दुनिया के सबसे बड़े खादी तिरंगे का अनावरण किया।

भले ही प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और निष्ठा है। मगर राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं और सम्मेलनों के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता की कमी अक्सर देखी जाती है। पूरे उत्साह के साथ और सभी समारोहों के बीच ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब राष्ट्रीय ध्वज क्षैतिज रूप से फहराया जाए, तो भगवा बैंड हमेशा शीर्ष पर दिखाई दे। इसे पानी या जमीन को नहीं छूना चाहिए। तिरंगा हमें हमारी राष्ट्रीय विचारधारा की याद दिलाता है, जिसने उस भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसे हम आज जानते हैं।

राज्य सरकार हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने जा रही है। इसमें आम बसों के साथ-साथ जल्द ही 550 इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी शामिल किया जाएगा।

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम से करने को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार में सहमति बनी है।

हरियाणा की समृद्धि में वृद्धि करेगा हथिनीकुंड बांध

पानी धरती का अमूल्य तत्व है। उचित प्रबंधन न होने की वजह से हर वर्ष बरसात के दिनों में यह अमूल्य तत्व बर्बाद हो जाता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है तथा बांध ओवरफ्लो हो जाते हैं। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड में बांध बनाने का निर्णय लिया है। इस बांध का कैचमेंट एरिया लगभग 11,170 वर्ग किलोमीटर होगा। बांध हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनाया जाना है। इसके बनने से हरियाणा को न केवल बिजली मिलेगी, बल्कि पानी की आपूर्ति भी हो सकेगी। अनुमान है कि यहां वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 एमयू हो जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग के समक्ष भेजने की मंजूरी दी।

केंद्र व पांच राज्यों को भेजी रिपोर्ट

केंद्रीय जल आयोग की आवश्यकता के अनुसार, डीपीआर तैयार करने के लिए सबसे पहले सीडब्ल्यूसी की 'सैद्धांतिक' सहमति प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। इसी कड़ी में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को अब केंद्रीय जल आयोग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भेजा जाना है।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

जल आयोग के अतिरिक्त यह रिपोर्ट पांच राज्यों में भी भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हथनीकुंड डैम हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में यह रिपोर्ट अहम मानी जा रही है।

हथनीकुंड बांध बनने से आस-पास के क्षेत्र में भूमिगत जलस्तर बढ़ेगा। इससे दूर दराज तक के खेतों को पानी मिलेगा और किसानों को अच्छी फसल मिलेगी। इसके अतिरिक्त यमुना नदी के क्षेत्र में हर वर्ष बारिश के दिनों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे किसानों की फसलें खराब हो जाती है। डैम बनने से बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। इस डैम के बनने का फ़ायदा रेणुका, किसाऊ और लखवार तीनों डैम को मिलेगा। इन तीनों डैम के पानी को संतुलित रखा जा सकेगा।

बांध के चारों ओर पर्यटन केंद्र भी बनाया जाएगा। कोई भी बांध पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। यह बांध जिस क्षेत्र में बनने वाला है, वह बेहद हरा-भरा और प्रकृति के करीब है। इसे पर्यटकों की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा।

- संवाद ब्यूरो

लम्पी स्किन से निपटने के लिए वैक्सीनेशन

प्रदेश के पशुओं में आई लम्पी स्किन बीमारी से निपटने के पर्याप्त इंतजाम किये जा रहे हैं। जिन जिलों में लम्पी स्किन बीमारी का अधिक प्रभाव है उन जिलों में सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। पशुपालकों को चाहिए कि ऐसे पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखें। तभी अन्य पशुओं को भी इस बीमारी से सुरक्षित रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल बीमारी से प्रभावित जिलों की खुद समीक्षा कर रहे हैं।

रोग के प्रभाव को रोकने एवं कम करने के लिए सबसे पहले एक जिले से दूसरे जिले में पशुओं की आवाजाही को रोकना चाहिए। विशेषकर जिन जिलों में फिलहाल इस बीमारी का ज्यादा प्रकोप है, वहां इस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। इस बीमारी के संबंध में ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को जागरूक होना होगा।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जे.पी.दलाल ने बताया कि प्रभावित जिलों के पशुपालकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के वैज्ञानिकों की मदद से इसकी रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है।

पशुपालकों के हितों को देखते हुए पशुओं में फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए पशुओं के टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया हुआ है। राज्य में कुल 19 लाख 32 हजार 39 पशुओं की संख्या है जिनके लिए पर्याप्त वैक्सीन का वितरण किया जा रहा है।

मछलीपालन का नया लक्ष्य

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जे.पी.दलाल ने कहा कि हरियाणा ने वर्ष 1966-67 में 58 हैक्टेयर पर मछलीपालन शुरू किया था। जो वर्ष 2021-22 में 19100 हैक्टेयर पहुंच गया है। इस वर्ष हरियाणा ने 2 लाख 9 हजार 33 मीट्रिक टन मछली उत्पादन किया है। हरियाणा सरकार ने इस बार उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाते हुए 2022-23 में 21650 हैक्टेयर रखा है। वहीं इसके अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे 2 लाख 10 हजार 500 मीट्रिक टन रखा गया है। सरकार इस निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मछलीपालकों को प्रोत्साहित कर रही है। उन्हें निरंतर नई-नई तकनीक से अवगत करवाया जा रहा है।

आउटलेट में गन्ने के उत्पादों की बिक्री

संगीता शर्मा

किसान अब अपने खेत का गन्ना शुगर मिल में बेचने के साथ-साथ गन्ना के उत्पाद बनाकर बेचने लगा है। पानीपत में एक मेगा मॉल के सामने किसान बिजेंद्र कादियान व दीपक कुमार ने गन्ने के उत्पाद को बेचना शुरू किया है। खास बात यह है कि वे यहां साधे कपड़े में नहीं, बल्कि कारपोरेट लुक में नजर आते हैं, ताकि ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। महीने पहले अढ़ाई लाख रुपए की लागत से उन्होंने स्टार्ट अप शुरू किया था। हाल ही में इन्होंने पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित कम्युनिटी सेंटर में 'ईट राइट मेला' में भी भाग लिया।

किसान अपने खेतों के शुद्ध व जैविक गन्ने से आउटलेट में गन्ने की चाय, कॉफी, जूस, आइसक्रीम चुश्की, गन्ना जलेबी गनेरी व गन्ना-इमली चटनी के उत्पाद बेच रहे हैं। एक बार जो ग्राहक गन्ने के जूस, चाय व अन्य उत्पाद चख लेता है वह दूसरी बार अवश्य उन उत्पादों को लेने आता है। इसमें वह चीनी व शक्कर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि गन्ने का रसीला स्वाद ही मिठास बढ़ाता है।

नागल खेड़ी गांव के बिजेंद्र ने बताया कि हरियाणा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है वह सराहनीय है। पांच-छह किसानों को मिलकर स्वयं का उत्पाद बेचकर अधिक मुनाफ़ा कमाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

बिजेंद्र बताते है कि साढ़े तीन साल से उन्होंने गन्ने के उत्पाद बनाने व मार्केटिंग स्किल सीखने व अन्य खाका तैयार करना शुरू कर दिया था। गन्ना विशेषज्ञ विपिन सरीन के संपर्क में आए और जैविक गन्ने की बिक्री के बारे में उनसे बात की। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के श्याम लाल से गन्ने के उत्पाद बनाने सीखे। घर की रसोईघर में गन्ना इमली चटनी बनाते है और आउटलेट में 300 एमएल बोतल की कीमत 250-300 रुपए तक की होगी। आउटलेट में दो ड्रिप फीजर, जूस, कैंपर, मिक्सी व इंडक्शन रखा गया है। सर्दियों में जैविक गुड़ बेचने की योजना भी बना रहे हैं।

स्वयं रोज़गार अच्छा साधन

दीपक कुमार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के साथ किसानों को खेतों से होने वाली आमदनी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कुछ नया करके दोगुना कमाना चाहिए। इसी मकसद से दोस्त के साथ मिलकर आउटलेट शुरू किया है। उन्होंने बताया कि यह आउटलेट शुरू करने से पहले गन्ने का उत्पाद बनाने के लिए पंजाब व अहमदाबाद से प्रशिक्षण लिया। अहमदाबाद से गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन खरीदकर लाये। अढ़ाई लाख रुपए से दोस्त के साथ मिलकर स्टार्ट अप शुरू किया है और आउटलेट का किराया व बिजली का बिल समेत 15,000 रुपए मासिक खर्चा है और गन्ने व अन्य उत्पादों का खर्चा अलग है। दीपक ने बताया कि कई साल सिक्योरिटी हैड के रूप में कार्य किया और यह नौकरी अधिक रास नहीं आ रही थी। कोरोना काल में तो नौकरी छूट गई और ऐसे में लगा कि नौकरी पर भरोसा करना ठीक नहीं है और यह कभी भी छूट सकती है। इसलिए खुद का काम करना चाहिए ताकि परिवार का गुजारा-बसर कर सके। उन्होंने बताया कि तीन महीने पहले ही आउटलेट शुरू किया है और गर्मियों में प्रतिदिन 5,000 रुपए आमदनी हो जाती थी व औसतन 1,000 रुपए है जबकि शनिवार व रविवार के दिन 1,500 से 2,200 रुपए आमदनी हो जाती है। उनका कहना है कि हम लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ का सेवन करवा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा कारोबार दिन-प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ता जाएगा।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल (awards.gov.in) के माध्यम से 15 सितंबर 2022 तक प्राप्त किए जाएंगे।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। देश में हल्दी उत्पादन के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

रोज़गार अवसरों का होगा सृजन, 3,500 करोड़ रुपए का निवेश

हरियाणा सरकार विदेशी निवेश राज्य में आकर्षित करने के लिए नित नये प्रयास करती रहती है। इस तरह की पहल से जहां एक ओर स्थानीय युवाओं को रोज़गार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होते है, वहीं दूसरी ओर इससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। इसी सोच को आयाम देने के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में स्वीडन के इंका सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आइकिया मिक्सड यूज कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर इसके निर्माण का शुभारंभ किया। लगभग 3,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले मिश्रित उपयोग वाले इस आइकिया प्रोजेक्ट का निर्माण गुरुग्राम के सेक्टर-47 में होगा। इस मौके पर स्वीडन के भारत में राजदूत क्लास मोलिन भी उपस्थित रहे।

रोज़गार और व्यापार के अवसरों में वृद्धि

यह प्रोजेक्ट उत्तर भारत तथा इस क्षेत्र के ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक विश्व स्तरीय रिटेल एवं लेजर गणतव्य होगा। इससे निवेश के साथ-साथ रोज़गार और व्यापार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। इस प्रोजेक्ट में इंका सेंटर्स 400 मिलियन पाउंड अर्थात् 3,500 करोड़ रुपए निवेश करेगा। यहां पर बेहतरीन रिटेल, वर्कस्पेस और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए स्पेस होंगे। प्रोजेक्ट से लगभग 2,500 नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। भारत में आइकिया जो भी बेचता है उसका 27 प्रतिशत वह स्थानीय स्त्रोतों से लेता है, जिसे आने वाले वर्षो में 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है।

कौशल विकास और शिक्षा की नीतियों में बदलाव

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज विश्व में नई तकनीक और डिजिटल इंटरफेस एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं जो नए अवसरों और चुनौतियों दोनों को खोल रही है। नई प्रक्रियाएं और नए उत्पाद आर्थिक विकास के नए रास्ते खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते औद्योगिक परिवेश में इनोवेशन तथा पारंपरिक उत्पादन हमारे युवा के लिए रोज़गार का बड़ा स्रोत रहेंगे। दूसरी तरफ़ हमारी मानव संसाधन को भी अपने स्किल को बढ़ाकर जीवन में बदलाव लाने की ज़रूरत है।

अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाना

आइकिया इंडिया की सीईओ सुसान पल्वरर ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में अपने व्यवसाय द्वारा लोगों, पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। इंका सेंटर्स के साथ हम होम फनीर्शिंग बाज़ार में वृद्धि करने में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे और लोगों को रिटेल का बेजोड़ अनुभव प्रदान करेंगे।

ई-गवर्नेंस: समय के साथ बढ़ते कदम

गुरुग्राम में पटवारियों को दिए टैबलेट

समय के साथ साथ तकनीक में भी क्रान्तिकारी बदलाव हुए हैं, पटवारियों को टैबलेट मिलने से काम पहले की अपेक्षा समय पर होने के साथ गलतियों की आशंका भी कम रहेगी। रिकॉर्ड का रख-रखाव भी ठीक प्रकार से हो सकेगा। अब पटवारी कोई भी गलती करेगा तो उसकी गलती टैबलेट के सॉफटवेयर के माध्यम से पकड़ी जाएगी। पटवारी का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है और यदि एक बार कोई भी डेटा रिकॉर्ड में गलत चढ़ जाए तो उससे लिटिगेशन शुरू हो जाती हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में पटवारियों व कानूनगो को ई-गवर्नेंस के तहत 67 टेबलेट वितरित किए। यह कार्यक्रम गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित किया गया था। इस दौरान उन्होंने पटवारियों को सावधानी व ठीक तरीके से काम करने की सलाह दी और कहा कि यदि ठीक से काम नही करोगे तो कंप्यूटर का जो जाल बिछा है उसमें गलतियां पकड़ी जाएंगी। अगर आप से ठीक काम करते हुए अनजाने में गलती हो जाती है तो उपायुक्त आपके पीछे खड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा योजना के तहत 85 लाख एकड़ भूमि पंजीकृत है और प्रत्येक इंच की किसानों को स्वयं द्वारा अपने खेत में बोई गई फसल की जानकारी देनी होती है। इतना ही नही, प्रदेश में हर परिवार का डेटा तैयार किया जा रहा है जिसमें व्यक्ति के आयु, जाति, आय आदि का विवरण होगा और उन्हें सरकारी सेवाओं का लाभ प्रोएक्टिव तरीके से दिया जाएगा । जैसे ही व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होगा तभी उसे सरकारी योजनाओं से डिजिटल माध्यम से जोड़ दिया जाएगा और उसे घर बैठे इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस प्रि या से रियल टाइम जनसंख्या का डेटा आना भी शुरू हो जाएगा।

'ई -गर्वनेंस' का एक अन्य उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अब राजस्व, मुख्यमंत्री का कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय तथा वित विभाग आदि कार्यालय ई-ऑफिस के माध्यम से चल रहे हैं। ऐसे ही जिन विभागों में पब्लिक डीलिंग ज्यादा है उन्हें भी ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। बताया कि पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा को भी ई-विधानसभा कर दिया गया है जिससे कागज की बचत होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि ई-गर्वेनेंस को बढ़ावा देते हुए प्रदेश में पिछले दिनों 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षा के 7 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट भी वितरित किए गए हैं जिससे इतने बड़े पैमाने पर टैबलेट वितरित करने वाला हरियाणा दुनिया का पहला प्रदेश बन गया है।

समय की बचत होगीः उपायुक्त

गुरूग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि पटवारी और कानूनगो को गिरदावरी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र से संबंधित कार्य जैसे कि जाति वैरिफिकेशन आदि फील्ड के कार्य करने होते हैं। ऐसे में पटवारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इसे डिजीटल करने का निर्णय लिया और पटवारियों के लिए 67 टैबलेट खरीदे गए। इन टैबलेट के सॉफटवेयर के माध्यम से समय की बचत होगी और लॉगनीट्यूड और लेटिट्यूड डिटेल के साथ वास्तविक समय के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। इस टैबलेट को पटवारी अपने साथ रखेगा और यदि भविष्य में पटवारी की ट्रांसफर भी हो जाती है तो उसके स्थान पर जो भी पटवारी ड्यूटी पर आएगा उसे वह टैबलेट दिया जाएगा।

किचन से कैंटीन तक पहुंची महिलाएं

संगीता शर्मा

महिलाएं अब घर का किचन में खाना बनाने व परोसने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब उन्होंने कार्यालयों, मंडियों, कॉलेजों व रेलवे स्टेशन में भी कैंटीन की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसमें एक महिला ही आत्मनिर्भर होने के साथ अन्य महिलाओं को भी आमदनी का साधन उपलब्ध करवा रही है। यह कैंटीन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचएसआरएलएम) के सहयोग से चलाई जा रही है। इनमें से पलवल स्थित मिनी सचिवालय की एक कैंटीन जहां गत वर्ष 'एकता' कलस्टर लेवल फेडरेशन के सहयोग से शुरू की गई थी, वहीं इस वर्ष पलवल के रहराना गांव की लीलावती स्वयं कैंटीन की कर्त्ता-धर्त्ता है। वह स्वयं सहायता समूह की छह महिलाओं व दो पुरुष हवलाई को रोज़गार उपलब्ध करवा रही है।

लीलावती वर्ष 2016 में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों के संपर्क में आई और 'ओउम' स्वयं सहायता समूह में शामिल हुईं। वर्ष 2017 में एक्टिवली स्वयं सहायता समूहों के गठन में जुट गई। महिलाओं को एकत्रित किया और कई कार्यशालाओं में भाग लिया। गांव-गांव में जाकर महिलाओं को हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया।

लीलावती ने बताया कि इससे पहले वह कभी घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं निकली थी और समूह से जुड़कर उसमें आत्मविश्वास आया और वह आत्मनिर्भर बन गई है। साथ ही उनके पति भीम सिंह भी कैंटीन के काम में उनके साथ कदमताल मिलाने में जुट गए हैं।

12 वीं पास लीलावती ने बताया कि 'एकता' स्टेट लेवल फेडरेशन की साझेदारी से मिनी सचिवालय में 'एकता' महिला कैंटीन 31 जुलाई 2021 में शुरू की, जिसमें एचएसआरएलएम के सहयोग से तीन लाख रुपए के अनुदान मिला। जिससे बर्तन, फ्रीज, करियाना का सामान व अन्य कैंटीन की ज़रूरत से संबंधित सामान खरीदें। कैंटीन का 10,000 रुपए मासिक किराया था। एक साल का कॉट्रेक्ट पूरा होने के बाद कैंटीन की बोली लगाई गई। लीलावती ने 19,000 रुपए मासिक किराया पर 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च 2023 तक कैंटीन चलाने की जिम्मेवारी ले ली। अब वह स्वयं और स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के सहयोग से कैंटीन चला रही है। उसने सीआईएफ से 50,000/- का ऋण अपनी कैंटीन चलाने के लिए लिया। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य सीमा, लक्ष्मी, सुषमा, प्रियांशी व सुनीता कैंटीन में हाथ बंटा रही हैं।

किसानों और मजदूरों को सस्ते दर में भोजनः

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमरेन्द्र कौर ने बताया कि मिशन की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न कार्यालयों में कुल 100 कैंटीन स्थापित की गई हैं। ये कैंटीन मिनि सचिवालय, श्रम विभाग, स्वास्थ्य केंद्रों, बस स्टैंड्स, कॉलेजों, रेलवे स्टेशन आदि में चलाई जा रही हैं। विभिन्न जिलों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। कुल 25 अटल किसान मजदूर कैंटीन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही है। इस कैंटीन का उद्देश्य मंडियों में किसानों और मजदूरों को सस्ते दर में भोजन उपलब्ध कराना है। भोजन का विक्रय मूल्य 10 रुपए प्रति प्लेट है, जिसमें चार चपाती, दाल, सब्जी और चावल शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उद्यमी एक-एक आईटीआई अडॉप्ट कर उसे स्पॉन्सर करें और उसे इंडस्ट्री की सहयोगी बनाएं। ऐसा करने से युवाओं को रोज़गार मिलेगा और उद्योगों को स्थानीय स्तर पर मैन पावर उपलब्ध होगी।

हरियाणा डेरी विकास सहकारी प्रसंघ ने वीटा बूथों पर मिठाइयां उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इस बारे में हल्दीराम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कम्पनी चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ समझौता हुआ है।

रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएगी फिल्म पॉलिसी

हरियाणा को कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर के रूप में देखा जाता था लेकिन हरियाणा फिल्म पोलिसी जारी होने के बाद प्रदेश का नाम कृषि, खेल और रक्षा क्षेत्र के अलावा फिल्मी क्षेत्र में भी पूरे सम्मान के साथ लिया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा जो फिल्म पोलिसी बनाई गई है वह बालीवुड जैसे प्रसिद्ध क्षेत्र की मशहूर हस्तियों से परामर्श करके बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से पिंजौर क्षेत्र में फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव है।

हरियाणा में लगभग 40 स्थान ऐसे हैं जो फिल्म शूटिंग के लिहाज से बहुत ही आकर्षक हैं। पिंजौर से लेकर नारनौल तक ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले इस प्रदेश की तरफ आने वाले समय में फिल्म उद्योग बहुत अधिक संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिल्मों को देश की एकता एवं अखंडता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों के बीच जुड़ाव पैदा होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस पोलिसी के तहत हरियाणावी फिल्में क्षेत्रीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ेंगी। उन्होंने फिल्म व्यवसाय को रोजगार के लिए अहम साधन बताया और कहा कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक भाषा की फिल्मों की हरियाणा में शूटिंग हो ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके।

नई दिल्ली में हरियाणा फिल्म एंड इंटरटेन्मेंट पालिसी के तहत जांच परख एवं मूल्यांकन कमेटी का सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में उन दर्जनों फिल्मों का अवलोकन हुआ जिनका फिल्म पालिसी के तहत अनुदान के लिए आवेदन हुआ है।

सेमिनार में कमेटी की अध्यक्ष फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ के अलावा फिल्म अभिनेता गजेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, राजीव भाटिया, गिरीश धमीजा, अतुल गंगवार व अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए।

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के महानिदेशक डा. अमित अग्रवाल ने इस अवसर पर सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

टूरिज्म को बढ़ावा देगी '48 कोस'

हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे भव्य कार्यक्रमों के साथ-साथ श्रीमद्भागवत गीता के संदेश को देश दुनिया में प्रचारित करने में हिंदी फिल्म '48 कोस' मील का पत्थर साबित होगी। फिल्म के लेखक, निर्माता-निर्देशक राजिंद्र वर्मा यशबाबू ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर यह फिल्म बनाई गई है, उसमें कामयाब हुई लेकिन चिंता की बात है कि कमर्शियल सिनेमा के चलते चंडीगढ़ में स्क्रीन तक नसीब नहीं हो पाई।

'48 कोस' - यह फिल्म समाज को एक सार्थक संदेश देने का काम करेगी। जिस प्रकार केंद्र और प्रदेश सरकार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित कर रही है, उन प्रयासों में हिंदी फिल्म 48 कोस भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिल्म में जिस प्रकार से गीता संदेश, ब्रह्मसरोवर के विहंगम दृश्य, गीता ज्ञान संस्थानम, गीता महोत्सव प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संदेश और बुराई पर सच्चाई की जीत और अहंकार को त्यागने जैसे विषयों को सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया गया है सही मायनों में यह जीवंत दृश्य और संदेश सही मायनों में '48 कोस' शीर्षक की सार्थकता साबित करते हैं।

गीता ज्ञान संस्थानम भी '48 कोस' में

फिल्म '48 कोस' की शूटिंग का कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र की गीता ज्ञान संस्थान में भी हुआ है। फिल्म में गीतामनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज और गीता ज्ञान संस्थान तथा संथानम के संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप के मनोहारी दृश्य भी फिल्म में नजर आ रहे हैं।

कुरुक्षेत्र की महिमा का प्रचार-प्रसार

लेखक, निर्माता, निर्देशक राजिंदर वर्मा 'यशबाबू' ने कहानी के संदर्भ में बताया कि बचपन से ही वह महाभारत से प्रभावित थे।

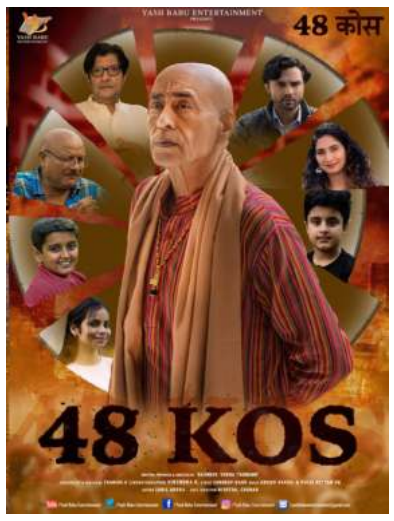

48 कोस के द्वारपाल यक्षों की कहानियां उनको बहुत आकर्षक लगती थी। इन्हीं कहानियों को वह आधुनिक रूप में दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। कहानी को अपने स्वरूप में आने में डेढ़ साल लगा। उन्होंने कहा कि अपनी फिल्मों के माध्यम से वे समाज को एक सकारात्मक संदेश देने के साथ-साथ कुरुक्षेत्र की महिमा का भी प्रचार-प्रसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं। उन्हें खुशी है कि उनकी यह फिल्म '48 कोस' के प्रचार-प्रसार और संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेगी।

हरियाणा और कुरुक्षेत्र के कई कलाकार शामिल

गौरतलब है कि 8 जुलाई को रिलीज हुई हिंदी फिल्म '48 कोस' में हिंदी सिनेमा के प्रख्यात कलाकार अनिल धवन, अरुण बख्शी, पंकज बेरी, रमन नासा, नलिनी खत्री के अलावा कुरुक्षेत्र के अनिल वर्मा, पारुल कौशिक, नरेश सागवाल, आशी खेत्रपाल, गर्वित खुराना, आरव वधवा, जय रल्हन, रितिका राय, योगिता पाल, मोनिका जौहर, विनोद यादव, संजीव चौहान, आदि फ़िल्म में नज़र आ रहे हैं।

सुण छबीले बोल रसीले

इलाज करणियां का टोटा कोन्या

रमलू के बाबू, मैरै खांसी-जुकाम होग्या, अस्पताल में चालकै दवाई दिवाल्या।

छबीला- भागवान, आपणा काढ़ा-कूढ़ा बणाकै पी ले, क्यों अस्पतालां के चक्कर कटवावै सै।

-दखे, तैरे कुछ होज्या तै भाजकै पीजीआई में जावैगा, मेरे दर्द नै तूं दर्द नहीं समझता।

-समझूं सूं मैडम, पर जड़े ताहीं घर तैं काम चालज्या, चला लेणा चाहिए। कोरोना में देख्या नहीं, जो परिवार काढ़े पीते रहे वे महामारी की चपेट में कोन्या आए। म्हारे काढ़े बहुत गुणकारी सैं। और ये तकरीबन सारे मसाले म्हारी रसोई में मिलज्या सैं। गजब की बात सै अक दूसरे देसां में रहणिये म्हारे देश के लोग भी बहुत कम कोरोना की चपेट में आए।

- मेरे भरतार, यू कोरोना कितोड़ तैं आग्या। मनैं खांसी जुकाम की दवाई दिवाल्या। पीजीआई में ना ले जाता तो पीएचसी में चाल।

- मैडम जी, पीजीआई में तो सारा दिन खपज्यागा। और पीएचसी में डाक्टर कोन्या पावै। दो बंटी गाम आळै बैद्य धोरै ल्याऊं?

- झोलाछाप डाक्टर की दवाई कोन्या ल्यूं। चालणा हो तो चाल, नहीं तो मैं एकली चली जाऊंगी।

रसीला आ जाता है। बोल्या- अरै छबीले के रौला कर रे सो?

- भाई रसीले, या रमलू की मां न्यू कहै सै अक पीएचसी में चालकै दवाई दिवाल्या।

- अरै बावळी, अनुलोम विलोम करले, कसर रहज्या तो प्राणायाम करले। सारे रोग ठीक होज्यांगे।

- बावली बूच, खांसी जुकाम में अनुलोम विलोम होया करै सै ?

- देख भाई छबीले, मैं जो जाणूं था वो कह दी। ईब थारी मर्जी।

- डटज्या रामदेव, मतन्या क्लेश करवावै, सांझनै रोटी नहीं थ्यावैंगी।

- छबीले भाई फेर तो न्यू करो, पीएचसी में चले जाओ। नए डाक्टर आए सैं, और बढ़िया दवाई दे सैं।

-आच्छा रै, पर ईब ताहीं तो इनमें डाक्टर कम पाया करते।

- भाई, सरकार नै स्वास्थ्य विभाग में साढ़े 800 डाक्टर और करीब अढ़ाई हजार पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती करी सै। इतणा ए नहीं, आख्यां के और दातां के डाक्टरां की भी भर्ती करी सै ।

ईब सरकारी अस्पतालां में ना तो इलाज करणियां की कमी और ना दवाइयां की कमी। कमी सै तो बस मरीजां की सै। मरीजां की कमी न्यू सै अक जिसकै भी छोटी-मोटी हरकत होज्या सै वोए शहर कान्या या पीजीआई कान्या भाजै सै। यो गलत बात सै। गाम के अस्पतालां में जो डाक्टर सैं वे किसे तैं कम कोन्या। पढ़े लिखे सैं। इन अस्पतालां में जाणा चाहिए।

- रसीले, क्या इन छोटे अस्पतालां में देसी दवाई भी मिलै सैं या केवल अंग्रेजी मिलै सैं?

- ईबै तो केवल अंग्रेजी मिलैं सैं। पर ज्यूकर सरकार नै घोषणा कर राखी सै अक तकरीबन सारी पीएचसी में आयुर्वेद विंग खोली जावैंगी तो भविष्य में देसी दवाई भी मिलण लागज्यांगी। सरकार लोगां की सेहत का पूरा ख्याल राखण लागरी सै। पर थाम ईब पीएचसी में जाओ और रमलू की मां की दवाई ले आओ। सरकार नै फ्री इलाज की व्यवस्था कर राखी सै। बड़ी बिमारी हो तो आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का इलाज फ्री होज्या सै। पर यो इलाज उनका होवैगा जिनके नाम बीपीएल सूची में दर्ज सैं।

- रसीले सरकार तो बहुत कुछ कर री सै। आए साल बहुत बड़ा बजट लोगां की चिकित्सा सेवाओं पै खर्च करै सै। पर लोगां नै भी आपणी सेहत का ख्याल राखणा चाहिए। जै बाबा रामदेव की मानकै रोज योग करैं तो कोए रोग ना होवै। खान-पान का ध्यान राखैं, योग करैं और मंडकै काम करैं तो के रोग कर लेगा। आपणा और सरकार का पीसा बचैगा।

-छबीले यो सारी बात ठीक, पर जो लोग सांझ होण की बाट देखैं और सांझ पाछै भींत पकड़ते चालैं सैं उनका के करैं?

- उननै उनके हाल पै छोड़द्यो भाई। सरकार किसे का हाथ पकड़ण कोन्या आवै। सुधरणा और बिगड़णा आपणे हाथ में हो सै। जिसा बोवैंगे उसा काट लेंगे। फिलहाल तूं मैडम नै लेकै दवाई दिवाल्या। नहीं तो फेर अस्पताल का टैम होज्यागा। टेस्ट करा, इलाज करा चाहे दवाई ले, हरियाणा सरकार नै सरकारी अस्पतालां में सबके लिए लगभग फ्री में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा राखी सै।

-आच्छा भाई जा सूं, तम कोन्या टिकण्द्यो। चालो मैडम जी चालो।

-मनोज प्रभाकर

शिक्षक दिवस पर

'गुरु महिमा'

गुरु कमाल दातार है, देते अमृत ज्ञान।
आगे गुरु प्रताप के, छोटे हैं भगवान।।

ज्ञान गुरु से सीखकर, बनता शिष्य महान।
दुनिया में गुरु ज्ञान से, मिलता नया विहान।।

दाता है गुरु ज्ञान के, सुनो लगाकर ध्यान।
बिना गुरु के नहीं मिले, दुनिया में बस ज्ञान।।

अमृत रस गुरु बांटता, पी ले भर-भर घूंट।
जो इसको ना पीवता, रहे ऊंट का ऊंट।।

कागज कोरा जानकर, गुरुवर लिखते लेख।
गुरु बड़े भगवान से, देख सके तो देख।।

समीप गुरु के बैठना, तजकर सब अभिमान।
गुरुवर देंगे प्यार से, दुनिया का सब ज्ञान।।

माता से ममता मिले, और बाप से प्यार।
मिले गुरु से ज्ञान जब, तब हो बेड़ा पार।।

तरवर फल देते हमें, नदियां देती नीर।
गुरुवर अपने ज्ञान से, हरते सारी पीर।।

गुरु आदि गुरु अंत है, गुरु का आर न पार।
ज्ञान बांट करके करे, गुरु हम पर उपकार।।

दुनिया में गुरु होत है, देखो रब का रूप।
नमन करें गुरदेव को, सुर, नर, मुनि सब भूप।।

- भूपसिंह 'भारती'

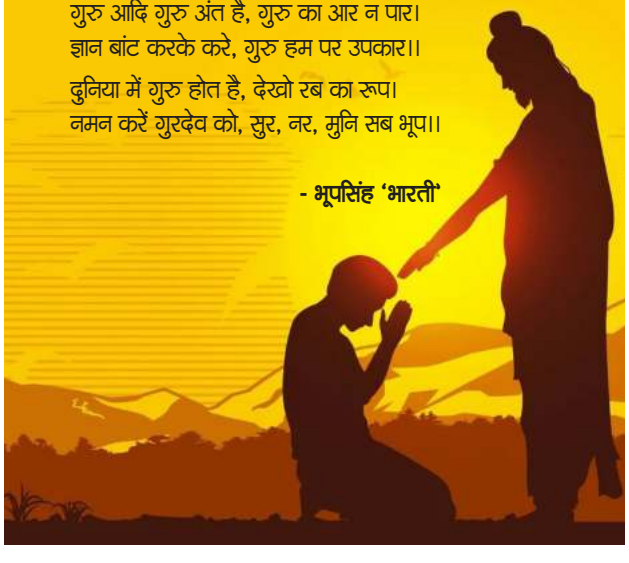

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com